



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी का कौशल आधारित शिक्षा दर्शन: NEP 2020 और IKS 2023 के संदर्भ में"

¹विवेक कुमार सुबुद्धि, ²डॉ. कृष्णा झरे, ³शिल्पी वर्मा

¹शोधार्थी, ²सह-प्राध्यापक, ³शोधार्थी

¹शिक्षाशास्त्र विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

²प्राच्य अध्ययन, धर्म अध्ययन एवं दर्शनशास्त्र विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

³योग विज्ञान और मानव चेतना विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

सारांश

शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का अर्जन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और व्यावहारिक कौशलों का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास पाठ्यक्रमों को शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य अंग बनाती है। यह नीति शिक्षा को रचनात्मकता, व्यावसायिकता और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की दिशा में कार्य करती है।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिक्षा दर्शन में भी कौशल-आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने केवल सैद्धांतिक शिक्षा की अपेक्षा व्यावहारिक, नैतिक और रोजगारपरक शिक्षा पर बल दिया। उनके विचारों में सामुदायिक भागीदारी, हस्तकला, कुटीर उद्योग और लघु व्यवसायों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात स्पष्ट रूप से मिलती है।

इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 में उल्लेखित कौशल विकास पाठ्यक्रमों का पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिक्षा दर्शन में विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि शिक्षा को कुटीर उद्योगों, हस्तकला, कृषि आधारित प्रशिक्षण और लघु व्यवसायों से जोड़ा जाए, तो यह रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और समाज के समग्र उत्थान में सहायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्किल एनहैंसमेंट कोर्स (SEC) के रूप में स्नातक स्तर पर कौशल विकास पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक कौशलों को सीखने और प्रमाणित रूप से अपने करियर को नई दिशा देने का अवसर मिलता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 (IKS 2023) एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में वर्तमान के आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। कौशल विकास पाठ्यक्रम के संदर्भ में IKS 2023 द्वारा पारंपरिक कौशलों को शिक्षा में समाहित करके विद्यार्थियों को हस्ता कला और भारतीय लोक कला आदि को जोड़कर पढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

अतः यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत मूल्य-आधारित, व्यावहारिक और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाली शिक्षा न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 के उद्देश्यों से मेल खाती है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाने में भी सहायक हो सकती है।

शब्द कुंजी - कौशल विकास, रोजगारपरक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा ।

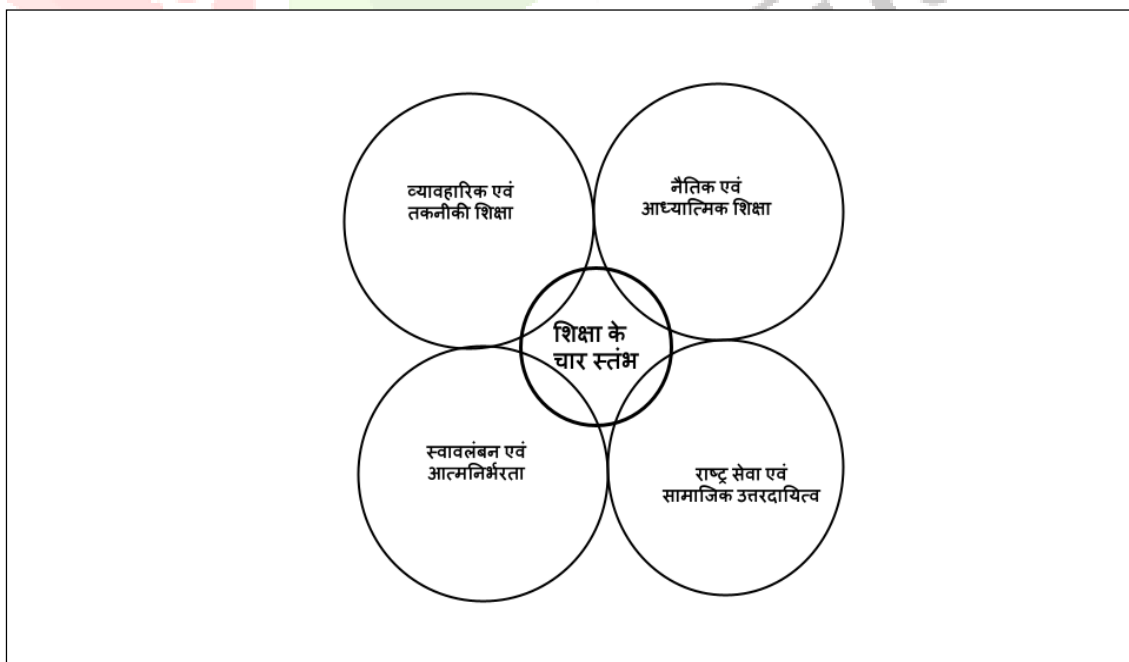
प्रस्तावना

शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें व्यावहारिक कौशल, नैतिकता और आत्मनिर्भरता का समावेश भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाती है। यह नीति विद्यार्थियों को उनके रुचि-आधारित कौशल विकसित करने, रचनात्मकता को बढ़ाने और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती है, जिससे वे अपने जीवन में स्वावलंबी बन सकें। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिक्षा दर्शन में भी कौशल विकास और व्यावहारिक शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का माध्यम न मानकर इसे व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन बताया। उनके अनुसार, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को रोजगारपरक, नैतिक और आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने अपने साहित्य में हस्तकला, कुटीर उद्योग, लघु व्यवसाय, कृषि-आधारित उद्योगों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है।

इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 में उल्लिखित कौशल विकास पाठ्यक्रमों और पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिक्षा दर्शन में कौशल विकास की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन यह प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार शिक्षा को कौशल-आधारित, रोजगारपरक और आत्मनिर्भरता से जोड़कर भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाया जा सकता है। यह शोध पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समन्वय की आवश्यकता को भी उजागर करेगा, जिससे एक व्यापक, समग्र और उपयोगी शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सके।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का शिक्षा दर्शन

शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता का माध्यम बननी चाहिए। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का शिक्षा दर्शन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें व्यावहारिक शिक्षा, नैतिकता, और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भी कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार सृजन को केंद्र में रखती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आचार्य जी के विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि समाजोत्थान और राष्ट्रनिर्माण भी होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को चार स्तंभों पर आधारित माना।



शिक्षा के चार स्तंभ

1. नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा – शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए।
2. व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा – जीवनोपयोगी कौशलों के बिना शिक्षा अधूरी रहती है।
3. स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता – शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
4. राष्ट्र सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व – शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समाज और राष्ट्र की सेवा होनी चाहिए।

युग निर्माण विद्यालय और कौशल विकास

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने 'युग निर्माण विद्यालय' की स्थापना की, जहाँ विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती थी, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों में कौशल विकास पर बल दिया जाता था। जिसका आज विस्तृत स्वरूप आचार्य श्री के शिक्षा दर्शन पर आधारित देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज आश्रम व देश भर में चल रहे कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण केंद्र हैं।

- कृषि एवं जैविक खेती
- हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग
- विद्युत एवं यांत्रिक प्रशिक्षण
- स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद
- स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग प्रशिक्षण

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी पारंपरिक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय स्वरोजगार को अपनाएं और आत्मनिर्भर बनें।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार शिक्षा के आवश्यक बिंदु

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का शिक्षा दर्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न होकर व्यावहारिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता, नैतिक मूल्यों और समाजसेवा पर केंद्रित था। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु निम्नलिखित क्रमबद्ध प्रयासों की आवश्यकता बताई—

1. प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाना

प्रत्येक नागरिक के लिए प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति बुनियादी साक्षरता और ज्ञान प्राप्त कर सके। यह शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे समाज में समानता बनी रहे।

2. राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण

सरकार को यह विश्लेषण करना चाहिए कि देश में किस प्रकार के कार्यों और उद्योगों में कितने लोगों की आवश्यकता है। इसके आधार पर शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि विद्यार्थी उसी दिशा में प्रशिक्षित हो सकें, जिससे उनकी शिक्षा और रोजगार की संभावनाएँ सीधे जुड़ी रहें।

3. उच्च शिक्षा के लिए योग्यता आधारित चयन

उच्च शिक्षा केवल उन्हीं छात्रों को मिलनी चाहिए जो योग्यता, प्रतिभा और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। केवल डिग्री प्राप्त करने की मानसिकता से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश न दिया जाए, बल्कि आवश्यकतानुसार और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा का अवसर दिया जाए।

4. रुचि एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर शिक्षा

विद्यार्थियों की रुचि, झुकाव और मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी किस विषय में अधिक रुचि रखते हैं और उसी के अनुसार उनका मार्गदर्शन किया जाए। इससे उनकी प्रतिभा का समुचित विकास होगा और वे अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगे।

5. 8वीं कक्षा के बाद विशेष अध्ययन की दिशा में मार्गदर्शन

यदि विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के बाद उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विशेष अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए, तो इससे उनका समय और धन दोनों की बचत होगी। इससे वे जल्दी दक्षता प्राप्त कर रोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे।

6. शिक्षा के साथ शारीरिक श्रम और कुटीर उद्योगों का समावेश

विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ श्रम एवं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। उन्हें कुटीर उद्योगों, हस्तकला, कृषि, यांत्रिक कार्यों आदि की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए ताकि वे स्वयं के लिए रोजगार के अवसर बना सकें और आत्मनिर्भर बनें।

7. श्रम की गरिमा और श्रमिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा

शिक्षित वर्ग को कम श्रम में अधिक वेतन मिलने और अशिक्षित श्रमिकों को कठिन श्रम के बावजूद न्यूनतम वेतन मिलने की सामाजिक विषमता को दूर करना आवश्यक है। श्रम को सम्मान मिले, श्रमिकों को उचित वेतन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो— ऐसी व्यवस्था शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विकसित की जानी चाहिए।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा प्रतिपादित ये सात चरण शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। यदि इन बिंदुओं को लागू किया जाए, तो शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम न रहकर, समाजोत्थान, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता का साधन बन जाएगी। उनकी यह दृष्टि आज भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में प्रासंगिक बनी हुई है, जो कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देती है।

ग्रामीण अध्ययन एवं सततता विभाग: कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता की ओर एक पहल

देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार में कौशल विकास को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शिक्षा दर्शन के आधार पर 21 जून 2004 को ग्राम प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई। इससे पूर्व, 1995 से 2004 तक शांतिकुंज (मातृ संस्था) में 'रचनात्मक प्रकोष्ठ' का गठन कर विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से युगक्रांति की ग्राम तीर्थ योजना को मूर्त रूप दिया गया। विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के पश्चात, 2018 में इस विभाग का नाम बदलकर 'ग्रामीण अध्ययन एवं सततता विभाग' कर दिया गया।

इस विभाग की दृष्टि ग्रामीण क्षेत्रों को सुसंस्कृत, व्यसनमुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण भारत के विकास का एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग ने कई प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिनमें भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का विश्लेषण, ग्रामीण विकास हेतु संसाधन व्यक्तियों का निर्माण, कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास, प्रशिक्षण एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचे की स्थापना तथा आत्मनिर्भरता हेतु कुशल गौशालाओं का एक प्रभावी नेटवर्क तैयार करना शामिल है।

ग्रामीण अध्ययन एवं सततता विभाग की यह पहल स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग, आत्मनिर्भरता और ग्राम्य जीवन के सतत विकास को केंद्र में रखती है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार सृजन को बल मिलेगा, बल्कि ग्राम समुदायों का संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान भी संभव हो सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने वाली नीति है, जो 34 वर्षों बाद पूर्ववर्ती शिक्षा नीति (1986) का स्थान लेने के लिए आई। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र, बहु-विषयी (Multidisciplinary), कौशल आधारित (Skill-Oriented) और लचीली (Flexible) शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को रोजगारपरक, अनुसंधानपरक और मूल्यों पर आधारित बनाना है। NEP 2020 के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर एवं रोजगार योग्य बनाना भी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

1. **प्रारंभिक स्तर पर कौशल विकास:** कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था में ही व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
2. **इंटरशिप एवं अप्रेंटिसशिप:** विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर इंटरशिप एवं अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि विद्यार्थी औद्योगिक अनुभव प्राप्त कर सकें।
3. **लचीला पाठ्यक्रम (Multidisciplinary Approach):** विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं और अकादमिक शिक्षा के साथ कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी अपना सकते हैं।
4. **डिजिटल शिक्षा एवं तकनीकी दक्षता:** NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्र ऑनलाइन माध्यमों से तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल सीख सकें।
5. **स्थानीय एवं पारंपरिक कौशल को बढ़ावा:** स्थानीय उद्योगों, कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प एवं कृषि आधारित कौशलों को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
6. **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा फ्रेमवर्क (NVEQF):** नीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल विकास ढांचे (National Vocational Education Qualification Framework) की परिकल्पना की गई है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
7. **गैर-पारंपरिक रोजगार के लिए प्रशिक्षण:** NEP 2020 में युवाओं को स्टार्टअप, उद्यमिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी आदि नवीनतम क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए गए हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 का कौशल विकास पाठ्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव

भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में वर्तमान के आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS 2023) कर रही है जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान परंपराओं को शिक्षा में पुनःस्थापित करना है। विद्यार्थियों को बहुआयामी, व्यावसायिक, संस्कारित एवं कौशलयुक्त बनाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) बल देती है, जो एक व्यापक नीति है। दोनों ही पहलों का उद्देश्य पारंपरिक कौशलों को शिक्षा में समाहित करके विद्यार्थियों को हस्ता कला और भारतीय लोक कला आदि को जोड़कर पढ़ाने, शिक्षा को रोजगारोन्मुख, संस्कारयुक्त, और स्थानीय सन्दर्भों से जुड़ा हुआ बनाना है।

पाठ्यक्रम में पारंपरिक कौशलों का समावेश इस तरह हो जिससे भारतीय कला, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग, संगीत एवं लोककला जैसे पारंपरिक कौशलों को स्कूली एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने का है।

NEP 2020 और IKS 2023 के अनुसार विद्यार्थी केवल एक विषय में विशेषज्ञ न होकर कई क्षेत्रों में दक्ष हो पायेंगे जिससे पारंपरिक चिकित्सा (जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी), कृषि परंपराएं, योग व ध्यान, लोक साहित्य व लोक संगीत को अन्य विषयों के साथ जोड़ा जाये, इससे शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की दूरी कम होगी।

'करके सीखना' के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर हस्तकला, बुनाई, कुम्हारी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण, गाँवों में जाकर ग्राम विकास कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रदान करके कौशल विकास का इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे यह केवल रोजगार तक सीमित नहीं हो, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी मदद कर सके, जिसका उल्लेख देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लक्ष्य और पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी के शिक्षा दर्शन में भी है कि कौशल-आधारित शिक्षा व्यवस्था भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जाने वाला माध्यम है।

आचार्य जी के शैक्षिक विचारों, NEP 2020 और IKS 2023 में समानता

• शिक्षा के चार स्तंभ: पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, NEP 2020 और IKS 2023 की दृष्टि से

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने शिक्षा को चार स्तंभों पर आधारित माना, जिनका स्पष्ट समावेश NEP 2020 और IKS 2023 में भी देखा जा सकता है:

शिक्षा के चार स्तंभ	पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का दृष्टिकोण	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023
नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा	शिक्षा केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का साधन भी होनी चाहिए।	शिक्षा में नैतिकता और मूल्य-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा	शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने हेतु तकनीकी व व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक है।	कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया गया है।
स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता	शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके और स्वरोजगार को अपनाए।	आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौशल विकास पर बल दिया गया है।
राष्ट्र सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व	शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समाज और राष्ट्र की सेवा होना चाहिए।	शिक्षा को सामाजिक और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम न होकर समग्र विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का साधन होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को चार स्तंभों पर आधारित माना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 से मेल खाते हैं। पहला स्तंभ **नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा** है, जिसमें आचार्य जी ने चरित्र निर्माण को प्रमुखता दी, जबकि NEP 2020 और IKS 2023 में नैतिकता और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा स्तंभ **व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा** है, जिसके तहत आचार्य जी ने जीवनोपयोगी कौशलों पर जोर दिया, वहीं NEP 2020 और IKS 2023 ने कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। तीसरा स्तंभ **स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता** है, जहाँ उन्होंने स्वरोजगार को आवश्यक बताया, NEP 2020 और IKS 2023 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। चौथा स्तंभ **राष्ट्र सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व** है, जिसे आचार्य जी ने शिक्षा का अंतिम लक्ष्य माना, और इसी भावना के अनुरूप NEP 2020 और IKS 2023 में शिक्षा को सामाजिक व राष्ट्रीय विकास से जोड़ा गया है। स्पष्ट है कि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है NEP 2020 और IKS 2023 में उनकी विचारधारा का समावेश देखने को मिलता है। IKS 2023 के प्रस्ताव पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है जिससे भारत की पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान परंपराओं को शिक्षा में पुनःस्थापित किया जा सकेगा।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सुधार के सात चरण और NEP 2020 में समानता

शिक्षा सुधार के चरण	पं. श्रीराम शर्मा आचार्य की अवधारणा	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाना	प्रत्येक नागरिक को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।	प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया गया है।
व्यावसायिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण	देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रणाली का निर्माण होना चाहिए।	उद्योगों और शिक्षा प्रणाली के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।
उच्च शिक्षा के लिए योग्यता आधारित चयन	उच्च शिक्षा केवल योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को दी जानी चाहिए।	मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है।
रुचि आधारित शिक्षा प्रणाली	विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार विषयों का चयन किया जाना चाहिए।	मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया गया है।
8वीं कक्षा के बाद विशेष अध्ययन का मार्गदर्शन	विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।	स्कूली शिक्षा में इंटरनशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़ा गया है।
शारीरिक श्रम और कुटीर उद्योगों का समावेश	शिक्षा के साथ-साथ श्रम और हस्तशिल्प का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	व्यावसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य किया गया है।
श्रम की गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा	श्रमिकों को उचित वेतन और सम्मान मिलना चाहिए।	सामाजिक समावेशन और श्रम की गरिमा को बढ़ावा दिया गया है।

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शिक्षा दर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और भारतीय ज्ञान परंपरा 2023 (IKS2023) में कई समानताएँ देखने को मिलती हैं। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया, जिसे NEP 2020 और IKS 2023 ने सार्वभौमिक शिक्षा के रूप में लागू किया। व्यावसायिक आवश्यकताओं के सर्वेक्षण के माध्यम से उन्होंने शिक्षा प्रणाली को देश की जरूरतों के अनुसार ढालने की बात कही, जिसे NEP 2020 और IKS 2023 ने उद्योग-शिक्षा समन्वय के रूप में अपनाया। उच्च शिक्षा में योग्यता आधारित चयन पर उनका विशेष बल था, जिसे नीति ने मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया से जोड़ा। उन्होंने विद्यार्थियों की रुचि आधारित शिक्षा पर बल दिया, जिसे NEP 2020 ने मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में लागू किया। 8वीं कक्षा के बाद विशेष अध्ययन और मार्गदर्शन की उनकी अवधारणा को नीति ने इंटरनशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में अपनाया। शिक्षा के साथ शारीरिक श्रम और कुटीर उद्योगों के समावेश को आचार्य जी ने आवश्यक बताया, जिसे NEP 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और

अप्रेटिसशिप के रूप में अनिवार्य किया गया। अंततः, उन्होंने श्रम की गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर बल दिया, जिसे नीति ने सामाजिक समावेशन के माध्यम से मजबूत किया। स्पष्ट है कि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शिक्षा सुधार संबंधी विचार आधुनिक शिक्षा नीति में भी प्रतिबिंबित होते हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौशल विकास कार्यक्रमों का एकीकृत दृष्टिकोण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को समुचित रूप से लागू किया जाए, तो न केवल युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि वे स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शिक्षा दर्शन के अनुरूप यदि व्यावसायिक शिक्षा को समाजोत्थान एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा और राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। परिश्रम करने के प्रति जो दृष्टिकोण आज का शिक्षित वर्ग अपनाने लगा है, वह हीनतम वृत्ति है। शिक्षितों की बेरोजगारी समस्या के हल में यह एक व्यापक मनोवैज्ञानिक अवरोध है। अंग्रेजी हुकूमत ने ऑफिस में काम करने वाले बाबुओं को प्रतिष्ठा दी, वह अब भी भारतीय मानस में बैठी चली आ रही है। बाबूगिरी का काम करने वाले, कुर्सी पर बैठकर कलम घिसने वाले व्यक्ति बड़े होते हैं तथा शारीरिक श्रम करने वाले, छोटे-मोटे काम करने वाले छोटे। यह बेतुकी मान्यता आज भी अपने देश में प्रचलित है। राष्ट्रीय मानस से जब तक इस ग्रन्थि को नहीं निकाल फेंका जाता, तब तक बेरोजगारी की समस्या का हल आकाशकुसुम ही बना रहेगा। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के शिक्षा दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई समानताएँ हैं। यदि आचार्य जी के विचारों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाविष्ट किया जाए, तो न केवल युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार, उनके विचारों को अपनाकर हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. आचार्य, श्रीराम शर्मा (1973) युग निर्माण की रूपरेखा एवं कार्यपद्धति। मथुरा: युग निर्माण योजना प्रकाशन, पृ. 14
2. आचार्य, श्रीराम शर्मा (1990) परिवार और उसका निर्माण (द्वितीय संस्करण)। मथुरा: युग निर्माण योजना प्रकाशन, पृ. 10
3. आचार्य, श्रीराम शर्मा (1991) शिक्षा ही नहीं विद्या भी। हरिद्वार: शांतिकुन्ज, पृ. 5
4. ब्रह्मवर्चस (1991) शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वित स्वरूप। हरिद्वार: शांतिकुन्ज, पृ. 15-16
5. ब्रह्मवर्चस (1998) शिक्षा एवं विद्या। मथुरा: अखण्ड ज्योति संस्थान, पृष्ठ-1.8
6. पाण्डेय, रामशकल (2000) मूल्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। मेरठ: सूर्या पब्लिकेशन, पृ. 52
7. आचार्य, श्रीराम शर्मा (2004) नैतिक शिक्षा (भाग-2)। मथुरा: युग निर्माण योजना प्रकाशन।
8. अरोरा, ममता (2008) आचार्य श्रीराम शर्मा का सर्वांग शिक्षा दर्शन एवं उनके शिक्षा संबंधी प्रयोगों का मूल्यांकन (अप्रकाशित पी-एच.डी. शोध)। कानपुर: शिक्षा विभाग, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय।
9. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। (2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पहल। नई दिल्ली: भारत सरकार
10. <https://www.dsvv.ac.in/>
11. <https://www.oneindia.com/india/new-education-policy-2020-advantages-and-disadvantages-of-nep-3127811.html>
12. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020
13. https://www.iksindia.org/2023-2024_BGSamvardhanaYojana_Research_Final_25Jun23.pdf
14. https://iks.aicte-india.org/BGSamvahan-karyakram-20_2023_ENG.pdf